ALL-INDIA SERVICES REGULATIONS (INDEMNITY) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next Bill which we are going to take has had an eventful history. It was first passed by Rajya Sabha. It came before this House as long back as 15th December, 1972. It was first considered here and the consideration was not completed on that day. It was adjourned. There was a motion for resumption of the debate on 20th December, 1972 and the motion for consideration was adopted on that day. We were considering the clauses when we adjourned and it is now more than two years when we resume clause-by-clause discussion.

I find my good friend, Mr. Banerjee, was on his legs. He is not present at the moment. Then there is an amendment by Mr. Naik. He is also not present. There is probably nobody else who wants to speak. So, there is no amendment to Clause 2.

The question is:

"Clause 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1—(Short title and commencement).

Amendment made:

Page 1, line 4,—

for "1972" *substitute* "1975" (2)

(Shri F. H. Mohsin)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Twenty-third" *substitute*- "Twenty-sixth"

(Shri F. H. Mohsin)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be Passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री मूल चंद डागा (पली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट रेजिस्लेशन के बारे में अपने रूल्स आफ प्रोसीजर ऐंड कांडक्ट आफ बिजनेस में दिया है :

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned *sine die* and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act.

Where the specified period is not so completed, the regulation, rule, sub-rule, by-law etc. shall be re-laid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in the session."

15.10 hrs.

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*].

MR. CHAIRMAN: Which rule you are quoting?

SHRI M. C. DAGA: It is Rule 234.

जब कभी कानून बनाये जाते हैं और उन के अन्तर्गत रेगुलेशन्ज़ बनाने होते हैं तो इस के करने के दो तरीके है—हम लोगों ने क्या किया है? चूंकि पार्लियामेन्ट इतने लम्बे अर्से तक नहीं बैठती है तो या तो हम अपनी एक्ज़ीक्यूटिव एजेन्सीज़ को इस काम को सौंप दें जो इस काम को करें, आर्टिकल 309 में जहां सर्विसिज़ के रूल्ज़ बनते हैं, उन का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वे रूल्ज़ ए रेगुलेशन्ज़ बना कर हमारे सामने रख दें लेकिन होता क्या है—आप ज़रा सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट्स को देखिए—जो भी रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्स बनते हैं, हमारे सामने नहीं आते। कई बार तो बनते ही नहीं और बनते हैं तो सालों तक सदन की टेबिल पर नहीं रखे जाते, सब लोग चुप बैठे रहते हैं। हम लोगों को इस में एक पावर है—अगर ये रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ रख दिए जांय तो हम उन के सम्बन्ध में अपने आब्जेक्शन्ज़ फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब मोहसिन साहब कहते हैं—हमने अब तक जो कुछ किया है, उस को भूल जाओ, हमारा कुसूर माफ़ करो, नये सिरे से नई बात को याद रखो।

मैं चाहता हूं कि आप सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट्स को देखिए—उस ने कई बार इस बात को दोहराया है। कभी कभी तो एक्ज़ीक्यूटिव एजेन्सीज़ कम्पलाई ही नहीं करतीं। हम ने इस बात के लिए कई बार लिखा है, होम मिनिस्ट्री ने भी लिखा है कि जो भी रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ बनाये जांय वे सदन की टेबिल पर रखे जांय। मेरे पास एक नहीं हज़ारों-लाखों उदाहरण हैं जहां लोगों को नौकरी पर ले लिया गया है। जिस वक्त किसी को लेना हुआ, रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ बनाये, अमेण्ड किये और सर्विस में ले लिया, किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसी हालत में जब रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ हमारे सामने आयेंगे ही नहीं, तो हम आब्जेक्शन क्या फाइल करेंगे।

ऐसा किस लिए होता है? जब किसी आफिसर का, सैक्रेटरी हो, ज्वाइन्ट सैक्रेटरी हो, डिप्टी सैक्रेटरी हो या कोई दूसरा आफिसर हो, अपने किसी आदमी को नौकरी में लेना होता है तो रूल्ज़ एण्ड रेगुलेशन्ज़ को अमेण्ड कर के नौकरी में ले लेते हैं। उस के बाद कहते हैं कि हम ने रूल्ज़ को अमेण्ड कर दिया है। जब पूछा जाता है कि कैसे ले लिया तो कहते हैं कि हम ने अमेण्ड किया था, अब इस को रेगुलराइज़ कर दीजिये ऐसे एक नहीं हज़ारों केसेज़ हैं—हमारी सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी ने इस की जांच की है और पता लगाया है कि हमारी सरकार के उच्चतम अधिकारियों ने अपने लोगों को सेवा में लेने के लिए ऐसा किया है। आज आप इस बात को देखिए—गवर्नमेंट सर्वेन्ट के घर में जो भी होता है उस को सरकारी नौकरी मिल जाती है—उस का बेटा भी नौकरी में होगा, उस का भाई भी नौकरी में होगा, सब लोग नौकरी में होंगे, लेकिन गांव के या किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। एक कुनबा बना हुआ है—उच्चतम अधिकारियों के लोग ही नौकरी में आ जाते हैं, दूसरे लोगों को उस से बंचित रखा जाता है। हो सकता है—कभी कभी आप की इंस्ट्रक्शन्ज़ भी हो सकती है, लेकिन उन को कोट नहीं करते हैं, रूल्ज़ अमेण्ड कर देते हैं, उस के बाद आदमी नौकरी

श्री मूल चन्द डागा

में आ जाता है। जब पूछते हैं कि क्यों रखा, तो कहते हैं कि इतने साल हो गये हैं, अब तो यह परमानेन्ट हो गया है, आप रेगुलराइज कर दी जिए।

सभापति महोदय, यह जो बिल पास होने जा रहा है—यह कोई छोटी सी बात नहीं है। गल्ती दूसरे लोग करते हैं और सिर पर आप के पड़ रही है। अब आप कह रहे हैं कि हम बिल लेकर आये हैं, इस को पास कर दो। हम भी कहेंगे—चलो, पास कर दो, जो हुआ सो हुआ।

कांस्टीचूशन में सर्विसिज ऐक्ट का जिक्र है—आर्टिकल 309 के अन्तर्गत सर्विसिज ऐक्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? आप के सर्विसिज एक्ट के न बनने के कारण जो एक्जीक्यूटिव एजेन्सीज हैं, वे मनमानी करती हैं, जिस को चाहते हैं रख लेते हैं और यही वजह है कि हमारी योजनायें फेल हो जाती हैं। काम्पीटेन्ट आदमी नहीं आ पाते हैं। अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा—इस के लिए क्या गारण्टी है? मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों पर गौर करें।

श्री आर० वी बड़े (खरगोन) : सभापति जी, शुरू में मैंने जो भाषण दिया था, उस में एक-दो बातें रह गई थीं—अब मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो यह है कि आप ने बहुत सी आल इण्डिया सर्विसिज को—जैसे आइ० पी० एस०, आई० एफ० एस० को इस में लिया है, लेकिन जो एजूकेशन की आल इण्डिया सर्विसिज हैं उन को नहीं लिया है या इन्जीनियर्स की सर्विसिज को भी नहीं माना है—ऐसा क्यों है? इन को आप कब मानने वाले है?

जो महाविद्यालयों की सर्विसिज हैं उन को भी आप ने नहीं माना है—इस के बारे में भी आप कुछ ओपीनियन दें। इन सर्विसिज के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं।

तीसरी बात—स्टेट्स में जब आल इण्डिया सर्विसिज लागू होती हैं तो वहां आयु के बारे में झगड़ा पड़ता है—जैसे स्टेट्स में रिटायरमेन्ट की आयु 55 साल है और सेन्टर में 58 साल है—इस के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं।

SHRI F. H. MOHSIN: Sir, the suggestion made by Mr. Daga to lay before the House the rules framed under the various enactments made by Parliament is a good suggestion. Even in this Bill, the All-India Services Regulations (Indemnity) Bill, there is a provision made to lay before the House within a certain period the rules made under this Bill. It has been provided here:

"(2) Every rule made by the Central Government under this section and every regulation made under or in pursuance of any such rule, shall be laid, as soon as may be after such rule or regulation is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more sucessive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in such rule or regulation or both Houses agree that such rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation."

This provision is there and it will be our endeavour to place all the rules as early as possible after they are made.

With regard to the suggestion made by Shri Bade, about constituting an All-India Educational service, that is not relevant to the Bill. I must have notice for answering that question and so I am unable now to give an opinion on that question.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.20 hrs.

TOKYO CONVENTION BILL

MR. CHAIRMAN: we shall now take up the Tokyo Convention Bill.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR): I beg to move:

"That the Bill to give effect to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is a Bill which seeks to achieve mainly the objectives underlying the Convention on the Offences Committed on Board the Aircraft, which was adopted at Tokyo in 1963 under the auspices of the International Civil Aviation Organisation (ICAO). The Diplomatic Conference, which adopted the Convention, was attended by a representative of India, in view of the importance of the Convention. The Convention came into effect on December 4, 1969 on ratification by 12 States, as required by the Convention. With the increase in the incidents of hijacking, more and more States ratified the Convention, and presently 74 States are parties to it, including important States such as UK and USA.

The growth of international air transport has led to increasing concern as to the international aspects of the commission of offences on board aircraft. International air transport also raises the basic problem of the respective jurisdiction of national States over offences committed on board the aircraft as an aircraft during the course of its flight may fly over the high seas or territories which may not be subject to the jurisdiction of any one State, and may traverse the boundaries of more than one State in a short space of time. In such cases, it becomes difficult to ascertain exactly the place where the offence took place. Further, there were no international rules such as those applied to master of ocean going ship, in respect of the commander of an aircraft.

The atention of the International Civil Aviation Organisation had been engaged by these matters since 1950. These matters were considered by the Legal Commitee of ICAO from time to time and the final draft of the Convention produced by the Legal Committee was considered by the Diplomatic Conference held in Tokyo in 1963. The Convention was adopted with a view to partially solve these problems.

The Convention's major area of application is towards offences against penal laws or acts which jeopardise the safety of aircraft, and of passengers or property therein. However, offences against penal laws of a political nature, or those based on racial or religious discrimination, are excluded from the application of the Convention. It recognises that the State of registration of the aircraft is competent to exercise jurisdiction over offences and acts committed on board.

The Convention gives powers to the Commander of aircraft to use preventive measures such as restraint on passengers who commit penal